सो. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सीटू मजदूर

वर्ष 14 अंक 4 अप्रैल 1992 मूल्य : दो रुपये

सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग
नागपुर, 13-15 मार्च, 1992

अध्यक्षीय भाषण

ई० बालानन्दन

कामरेड,

मैं आप सब की ओर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए पुलिस गोलीबारी अथवा गुण्डों के हमलों में अपनी जान गंवाई । फरवरी 1991 में कलकत्ता में हुए सातवें सम्मेलन के बाद से दिवंगत हुए सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

सीटू ने सातवें सम्मेलन के बाद से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर घटने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मजदूर हितों के रक्षार्थ होने वाले संघर्ष में भाग लेना जारी रखा । हमने 1-3 सितंबर 1991 को दिल्ली में सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक तथा सातवें सम्मेलन के बाद किए गये कामों का जायजा लेने के बाद आगे के लिए लक्ष्य निर्धारित किये । उसके बाद की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी महा-सचिव की रिपोर्ट में है । मैं अपना वक्तव्य केवल कुछ मुद्दों तक ही सीमित रखूंगा ।

समाजवाद को लगा धक्का

हमने सातवें सम्मेलन में पूर्वी यूरोप में आए बदलावों तथा पूंजीवादी व्यवस्था पर उनके प्रभावों का जिक्र किया था । सोवियत संघ का विखंडन उसके भीतर मौजूद शक्तियों ने ही किया । हर गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है । हालांकि उन्हें स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल में शामिल कर लिया गया है लेकिन उनमें विभिन्न मुद्दों पर मतभेद हैं । नागानो कारवाक पर कब्जे को लेकर आर्मीनिया तथा अजरबैजान के बीच युद्ध जारी है । इस राष्ट्रमंडल में संयुक्त सैनिक कमान के बारे में कोई समझौता नहीं हो पाया । कजाकिस्तान व यूक्रेन जैसे देश अपनी स्वतंत्र सेना रखने पर बल दे रहे हैं, नौ-सैनिक शक्ति के नियंत्रण को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है । पांच इस्लामी गणराज्यों ने ईरान, तुर्की व पाकिस्तान द्वारा गठित इस्लामी गुट में शामिल होने का फैसला किया है ।

जिस उत्साह के साथ बाजार व्यवस्था का स्वागत हुआ था वह कठोर वास्तविकताओं से सामना होने पर मरने लगा है । जमाखोरी व कालाबाजारी आम बात हो गयी है । एक नया अमीर वर्ग उभर कर आया है जो बहुराष्ट्रीय संघों के साथ मिल कर काम कर रहा है ।

सोवियत अर्थव्यवस्था के तकनीकी पिछड़ेपन के बारे में बहुत प्रचार किया जाता था । लेकिन सोवियत अर्थव्यवस्था को जनता को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए विकसित किया गया था । अंतरिक्ष व परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण हैं । सोवियत टेक-नोलॉजी के पिछड़ेपन के खिलाफ इतना प्रचार किये जाने के बावजूद वहां के तकनीशियनों की बेहद मांग है । अब इन संसाधनों का उपयोग जनता के शोषण के लिए किया जाता है । बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए आ रही हैं तथा उनके उत्पादों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं । कई फैक्ट्रियों को बन्द करके अनेक मजदूरों को बेरोजगार बनाते हुए एक नया आर्थिक ढांचा खड़ा किया जा रहा है ।

सोवियत संघ में, चली आ रही सम्पूर्ण रोजगार, आवश्यक वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा सस्ती आवास योजनायें अब समाप्त कर दी गयी हैं । सभी चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गयी है । सोवियत संघ में कभी बेरोजगारी जानी नहीं गयी थी, और अब वहां लाखों लोगों को ठिठुरती ठंड में एक कप सूप के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है ।

रूस व अन्य गणराज्यों में सांस्कृतिक मूल्यों का विघटन हो रहा है । रिश्वतखोरी, चोरी व वेश्यावृत्ति बढ़ रही है । इन गंभीर समस्याओं के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया व्यक्त होने लगी है । श्रम संगठन वेतन-वृद्धि की मांग उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

अनेक इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। यह भी पता चला है कि कम्युनिस्ट अपने आपको पुन: संगठित कर रहे हैं तथा आगामी महीनों में सी.पी.एस.यू. की पार्टी कांग्रेस होगी।

पूर्वी यूरोप के देशों की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। अब उन्हें बाजार-अर्थव्यवस्था को चुनने की अपनी गलती का अहसास हो गया है। नवोदित पूंजीपति वर्ग विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिल अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है तथा रोजगार सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा के अन्य उपाय समाप्त हो गये आजकल पूर्वी जर्मनी व अन्य देशों में बेरोजगारी 25 से 40 प्रतिशत तक बतायी जाती है।

उन घटनाओं से न केवल मजदूर वर्ग को बल्कि पूरी मानव जाति को धक्का पहुँचा है। हमें मानव विकास में सोवियत संघ की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करना चाहिए।

सोवियत संघ के विघटन उसके बाजार-व्यवस्था में परिवर्तित होने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। तृतीय विश्व के देशों तथा मुक्ति आन्दोलनों ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना एक महत्वपूर्ण साथी खो दिया है। हम इस तथ्य को भुला नहीं सकते कि खुद हमारे देश को अपनी आजादी को सुदृढ़ करने तथा आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था के विकास में सोवियत संघ से महत्वपूर्ण सहायता मिली है।

1917 की महान अक्टूबर क्रान्ति की विजय ने मानव जाति की किस्मत बदल दी। विश्व के प्रथम समाजवादी देश ने अपने उदय से ही सम्पूर्ण मानव जाति की स्वतंत्रता, शांति व विकास का साथ दिया। क्रांति के बाद थोड़े से समय में ही सोवियत जनता के एक पिछड़े हुए देश के स्थान पर एक शक्तिशाली समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करके पूंजीवाद पर समाजवाद की श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध में फासिस्ट शक्तियों को पराजित करने के लिए सोवियत सेना ने अद्‌भुत शौर्य का प्रदर्शन करके व 20 मिलियन जनता ने कुर्बानियाँ देकर सम्पूर्ण मानवता की रक्षा की। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद बदले शक्ति सन्तुलन से एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमरीकी देशों को उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में बल मिला क्योंकि सोवियत संघ का एक शक्तिशाली उपनिवेशवाद विरोधी देश के रूप में उदय हुआ।

चीनी क्रान्ति भी, जिसके माध्यम से विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश समाजवादी खेमे में आ गया—अन्य बातों के ही समान सोवियत संघ से बल व प्रेरणा लेकर संभव हो पायी थी। विश्व भर के मजदूर वर्ग ने पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध अपने संघर्ष में समाजवादी व्यवस्था से प्रेरणा ली। इसी प्रकार इस बारे में भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि सोवियत संघ ने विश्व शान्ति की रक्षा करने व परमाणु विनाश को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

एक नयी समाजवादी व्यवस्था की स्थापना में हुई कुछ भूलों का लाभ उठाते हुए साम्राज्यवादी शक्तियाँ समाजवाद को विस्थापित कर पुन: पूंजीवाद को लाने में सफल हो गये हैं। चूंकि समाजिक विकास के नियम स्वयं अपने आपको साबित करेंगे अत: मजदूर वर्ग बहुत जल्द दूनी शक्ति से समाजवाद की स्थापना करेगा।

बहरहाल, हमें यह स्वीकार करना ही चाहिए कि यह केवल मजदूर वर्ग ही नहीं पूरी मानवता की विकास यात्रा को लगा एक धक्का है।

विश्व पूँजीवाद का संकट

बुर्जुआ विचारधारा हाल की घटनाओं को समाजवादी विचारधारा की असफलता तथा पूँजीवाद की सफलता के प्रमाण के रूप में देख रही है। वे दावा करते हैं पूंजीवाद के सभी आरंभिक संकटों को दूर कर लिया गया है तथा अब पूँजीवाद निरन्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है?

हम सभी जानते हैं कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ते हुए बाजार उत्पादन के आधार पर ही टिकी रह सकती है। उत्पादन में कमी या बाजार के सीमित होने का अर्थ है लाभ में गिरावट। इससे बाजार में घबराहट का माहौल बन जाता है। पूरे अस्सी के दशक भर विश्वव्यापी मंदी का खतरा मंडराता रहा है। अतः समाजवादी खेमे में ढहने से विश्व पूंजीवाद के बाजार नियोजकों द्वारा राहत के तौर पर ग्रहण किया गया है। लेकिन यह सब थोड़ी देर की बातें थीं। सभी बाजार विशेषज्ञों द्वारा अब यह बात स्वीकार कर ली गयी है कि पूंजीवादी व्यवस्था अब दीर्घकालिक संकट के दौर में प्रवेश कर चुकी है।

आधी शताब्दी से पूँजीवादी विश्व के अगुआ अमरीका की स्थिति इस संकट का प्रमाण है। अमरीका जो कि विश्व युद्ध के सबसे अमीर देश के रूप में उभरा था आज सबसे ज्यादा कर्ज के दबाव में है। दिसम्बर 1991 में अमरीका पर 360000 करोड़ डालर का विदेशी कर्ज आंका गया। यह राशि 10 माह की राष्ट्रीय आय के बराबर है। अपनी साथी पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार असंतुलन के चलते यह राशि और बढ़ती जा रही है। जापान इसका एक उदाहरण है जिसकी 800 करोड़ डालर कर्ज प्रतिवर्ष की दर है। लेकिन फिर भी अमरीका अपनी सैन्य क्षमता तथा विश्व भर में फैले अपने सैनिक अड्डों के बल पर नेता बना हुआ है।

पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट का नाम लेकर ईराक पर किया गया हमला, जिसका कर्ता-धर्ता अमरीका था, इसी संकट से उबरने तथा दुनिया पर अपनी दादागिरी बनाये रखने का एक प्रयास था। युद्ध के खर्चे के तौर पर अमरीका ने अपने जापान व ब्रिटेन आदि साथियों से 6500 करोड़ डालर वसूले। ऐसे युद्ध शताब्दी भर से पूँजीवादी की विशेषता रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा विश्व पर थोपे गये कोटियाई व वियतनामी युद्धों की याद लोगों के दिलों में बनी हुई है। युद्ध और विनाश से क्षति-उत्पादन के बोझ से दबे बाजार में पुन: जीवंतता आ जाती है और इस प्रकार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के असंतुलन के

उपाय की उम्मीद बनी रहती है।

लेकिन हाल के खाड़ी युद्ध से भी अमरीका व पूँजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का संकट दूर नहीं हुआ है। दरअसल, इससे संकट और बढ़ गया है। 1986 में अमरीका के आटोमोबाइल उद्योगों को 1500 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा व अपनी 11 उत्पादन इकाइयों को बन्द करना पड़ा। 1991 में इसके चेयरमैन रॉबर्ट स्टैम्पल ने 75000 मजदूरों को बेरोजगार बनाते हुए 21 और उत्पादन इकाइयों को बन्द करने की घोषणा की। सर्वाधिक सफल मानी जाने वाली 'बेथेल्गम स्टील्स' का 1991 का कुल घाटा 63800 करोड़ है और इसके एक एक चौथाई से अधिक मजदूर अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। आई बी एम जिसने 1990 में 6200 करोड़ डालर का लाभ कमाया, 1991 में 2800 करोड़ के घाटे में आ गयी और उसके 29000 मजदूर डिस्मिस कर दिये गये। इसके चेयरमैन जॉन एम्ल के अनुसार आई बी एम पिछले 4 वर्षों के अपने सबसे गंभीर संकट का सामना कर रही है। इसी प्रकार अन्य अनेक कम्प्यूटर कंपनियां जिनमें दूसरे नम्बर की कंपनी 'डिजिटल इक्विपटमेंट' भी शामिल है ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही हैं।

बढ़ते हुए घाटों से अमरीका के बैंक व वाणिज्य क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं और उसका बोझ बढ़े हुए करों के रूप में आम जनता को उठाना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ गयी हैं। नवम्बर 1991 में अमरीका के वाणिज्य क्षेत्र को पिछले वर्ष अक्टूबर के 60,300 करोड के घाटे के अतिरिक्त 30,600 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ है।

चूंकि अमरीकी अर्थव्यवस्था शून्य अथवा नेगेटिव विकास दर की समस्या से ग्रस्त है अतः इसके साथियों को भी विभिन्न प्रकार के संकट उठाने पड़ रहे हैं। जापानी अर्थव्यवस्था को विकास दर जो पहले बहुत अच्छी थी अब 1991 में घट कर पहली बार 3.8 पर आ गयी है। यह 1992 में 3 प्रतिशत तक गिर सकती है। अस्सी के दशक में जापान की व्यापार में अच्छी स्थिति थी जिसे वह और मजबूत करता जा रहा था लेकिन मंदी के वर्तमान दौर के चलते जापानी अर्थव्यवस्था भी समस्याओं का सामना कर रही है। जापान पर अमरीकी हितों वाली परियोजनाओं पर निवेश करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, और इस दबाव के जापानी सरकार द्वारा रखे गये प्रस्तावों का वहां की जनता द्वारा डटकर विरोध किया जा रहा है।

1990 में जब 1.7 करोड़ आबादी वाले पूर्वी जर्मनी का 6 करोड़ से अधिक की आबादी पश्चिम जर्मनी के साथ विलय हुआ था, तब संयुक्त जर्मनी यूरोप की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता हुआ प्रतीत हुआ था। जापान की ही तरह अस्सी के दशक में संयुक्त जर्मनी की अच्छी विकास दर थी। समाजवादी जर्मनी के जबर्दस्ती विलय से यह उम्मीद की गयी थी कि पूर्वी जर्मनी के तथाकथित पुनर्गठन के नाम पर पश्चिम जर्मनी के इजारेदारों को लाभ कमाने के खूब अवसर मिलेंगे। पूर्वी जर्मनी में भारी निवेश की योजनाएं थी तथा खूब लाभ की आशाएं लगायीं गयीं। अब ये सभी उम्मीदें धरी रह गयी हैं। जर्मनी की पूंजीपति पूर्वी जर्मनी के लोगों में जगायी गयीं आशाओं पर खरे उतरने में नाकाम रहे हैं और अब पूरा ढांचा दबाव में है। अब उस देश के औद्योगिक व वित्तीय इजारेदार मजदूरों के साथ एक असफल संघर्ष में उलझ गये हैं। विश्वव्यापी मंदी को देखते हुए अब जर्मन अर्थव्यवस्था के समक्ष भी शून्य अथवा नेगेटिव विकास दर की संभावनाएं उत्पन्न हो गयी हैं, पूर्वी जर्मनी के बहुप्रचारित व्यापक पुनर्गठन की बातें खोखली साबित हो गयी हैं।

अपने साम्राज्यवादी साथियों की तुलना में युद्ध से पहले की विश्व शक्ति—ब्रिटेन—की अर्थव्यवस्था में भी युद्ध के बाद के समय में ठहराव पैदा हुआ है। इस साम्राज्यवादी शक्ति के इजारेदार पूंजीपतियों द्वारा प्रचार किया गया कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की सभी युद्धोत्तर समस्याओं का समाधान थैचरवाद है। मार्गरेट थैचर के निर्देशों पर गैर-राष्ट्रीयकरण की एक प्रक्रिया आरंभ की गयी। विद्युत, टेलकॉम व स्टील आदि के कई बिलियन पौंड के संसाधन निजी मालिकों को बेच दिये गये। ब्रिटिश राज्य अपनी साम्राज्यवादी छवि को नष्ट होने से चिंतित था और उसी छवि को जीवित रखने के लिए व फॉकलेण्ड युद्ध जैसी गतिविधियों में संलग्न हुआ। लेकिन इस थैचरवाद को आर्थिक वास्तविकताओं के आगे झुकना ही पड़ा। थैचरवादी सुधारों के बाद 1991 तक प्रत्येक 50 फैक्ट्रियों में से एक दिवालिया घोषित होती गयीं। 1945 के बाद से इनकी संख्या 19,335 तक पहुंच गयी। दरअसल समाजवादी खेमे के ध्वस्त होने के तुरन्त बाद थैचर को कंसर्वेटिव पार्टी की छवि को बनाए रखने के लिए झुकना पड़ा। साम्राज्यवादी खेमे के प्रमुख सदस्य ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी संकट के दौर से गुजर रही है।

पूँजीवादी समुदाय का एक भी देश ऐसा नहीं है जो इस व्यापक संकट से अछूता, जिसके विश्वव्यापी मंदी का रूप लेने की आशंका है। ऐसी ही मंदी 1930 में आयी थी जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध था। संक्षेप में, विश्वव्यापी पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की यही तस्वीर है।

रोजगार व वेतन पर आघात

दीर्घकालीन आर्थिक संकटों के कारण पूँजीवाद अब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए योजनाएं बना रहा है। निजी इजारेदारों द्वारा विश्वव्यापी सुधारों के तहत अमरीका में लाखों मजदूरों की छंटनी कर दी गयी है। विकसित पूंजीवादी देशों के उद्योगपतियों द्वारा मिलकर विभिन्न देशों के मजदूर वर्ग पर हमले की योजना बनायी गयी है ताकि इस दबाव को बिना किसी प्रतिरोध के मजदूरों पर थोपा जा सके। जहां यूरोपीय आर्थिक समुदाय के माध्यम से मिलकर काम कर रहे है वहीं अमरीकी उद्योपतियों ने पहले से ही विस्तृत अमरीकी बाजार को कनाडा, मेक्सिको व मध्य अमरीका के कुछ राज्यों तक

फैलाने का निश्चय किया है और जापान भी दक्षिण-पूर्व एशिया में पीछे नहीं रहना चाहता।

अधिग्रहण, हस्तांतरण व रेड के एक दशक के बाद अब विश्व के वित्तीय-औद्योगिक इजारेदार इन तीनों क्षेत्रों को और मजबूत करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। प्राथमिक उद्देश्य विश्वव्यापी श्रम बाजार तथा उत्पादन व्यवस्था की मार्फत छंटनी व काम के घंटे बढ़ाकर वेतन लागत को कम करना है।

दिसंबर 1991 तक ब्रिटेन में बेरोजगारी 25,00,000 तक पहुंच गयी है। इस संख्या में सर्वाधिक वृद्धि पिछले चार महीनों में यानी अगस्त-दिसंबर में हुई, जिसमें अकेले नवंबर माह के 38,000 तक है। पिछले 20 माह से बेरोजगारी में वृद्धि का क्रम अनवरत रूप से जारी है। अब स्थिति यह हो गयी है कि कुल श्रम शक्ति का 8.7 प्रतिशत बेरोजगार है।

लेकिन ब्रिटेन के उपर्युक्त आँकड़े कुछ भ्रामक हैं। 1987 से सरकार ने मौसमी मजदूरों (Seasonal Workers) को एक तबके को रोजगार याफ्ता लोगों में शुमार करना शुरू कर दिया है। वर्तमान में मौसमी मजदूरों की संख्या 25,13,000 तक है इनमें से 74,4000 को पिछले एक वर्ष से किसी भी मौसम में कोई काम नहीं मिला। यदि इस संख्या को भी जोड़ा जाए जाए तो बेरोजगार कुल श्रम शक्ति का 13.6 प्रतिशत होंगे। इसके बाद फरवरी 1992 में 7500 और मजदूर बेरोजगार हो गये।

आधिकाधिक सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में स्पेन में सर्वाधिक बेरोजगारी है जहां 15.0 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। इसके बाद इटली (9.9 प्रतिशत), फ्रांस (9.5 प्रतिशत) तथा पश्चिम जर्मनी (6.4 प्रतिशत) का स्थान है।

मैं अमरीका में बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों के बन्द होने का पहले ही जिक्र किया था वहां बेरोजगारों की संख्या 6.8 से 10 प्रतिशत बतायी जाती है। जापान का साम्राज्यवादी देशों में से सबसे कम बेरोजगारी वाला देश होने का रिकार्ड था लेकिन वहां भी स्थिति तेजी से बदल रही है। अक्टूबर 1991 से जनवरी 1992 के बीच तीन बड़ी कंपनियां बन्द होने से जापान में 2,500,000 लोग बेरोजगार हो गये। जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र 'अकेहता' अपनी 29 जनवरी की संपादकीय टिप्पणी में लिखता है कि जापान के वर्ष में 2159 घंटे काम करने वाले मजदूरों को समान वेतन के लिए अपने अमरीकी साथियों के मुकाबिले 200 घण्टे ज्यादा तथा जर्मन मजदूरों के 5.0 घण्टे ज्यादा काम करना पड़ता है। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और घाटे को देखते हुए जापानी उद्योगपति काम के घण्टे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जापानी संसद ने यह कानून पास कर दिया है कि मजदूर वर्ष में 200 घण्टे अधिक काम करें।

विश्वव्यापी इजारेदारों की योजनाएं भी ठीक इसी दिशा में काम कर रहीं हैं पूंजीपतियों की इन योजनाओं के तहत आर्थिक शक्ति एवं विश्व उत्पादन प्रणाली चन्द हाथों में सिमटती जा रही है। इरादा एक ऐसे उत्पादन प्रणाली को विकसित करना है जिसके तहत मुट्ठीभर इजारेदार मार्केटिंग, रिसर्च से लेकर सभी चीज अपने नियंत्रण में रख सकें। डाटा कम्युनिकेजन नेटवर्क से अब उनके लिए यह संभव हो गया है कि अनावश्यक गतिविधियों को मध्यम-स्तर के उत्पादकों या स्व-रोजगार याफ्ता लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। इस प्रकार पूँजी के अनावश्यक व्यय से व फालतू श्रम शक्ति के बोझ से बचा जा सकेगा। योजना यह है कि स्थायी नौकरियों में कम से कम लोगों को रखा जाए बाकी लोग अनौपचारिक श्रम बाजारों में अपना श्रम बेचने के लिए छोड़ दिये जायेंगे जहां उनका अधिक शोषण होगा व ये लोग बड़ी कम्पनियों को सस्ती वस्तुएं बना कर उपलब्ध करायेंगे। अमरीका जैसे देश में भी मौजूदा कल्याण व श्रम कानूनों को भी इस हिसाब से बदला जा रहा है ताकि इन योजनाओं को कार्यरूप प्रदान किया जा सके।

साम्राज्यवादी देशों में भी घाटे की विकास दर व्याप्त रही है बुर्जुवा अर्थव्यवस्था की प्राचीन अवधारणाओं के विरुद्ध मुद्रा-स्फीति में कोई कमी नहीं आयी है। ब्रिटेन व अमरीका में, जहां घाटे के विकास दर रही है, जहां क्रमशः 4.7 व 3.8 प्रतिशत की मूल्य-वृद्धि हुई है। अस्सी के दशक में जापान में मुद्रास्फीति की दर कम थी लेकिन 1991 में वहां 3.5 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जर्मनी में 3.5 प्रतिशत, इटली में 6.3 प्रतिशत तथा स्वीडन में 8.2 प्रतिशन मूल्य-वृद्धि हुई। स्विट्जरलैण्ड में भी जहां परंपरागत रूप से कम मुद्रास्फीति रहा करती थी 1991 में 6 प्रतिशत मूल्य-वृद्धि हुई।

विकसित पूंजीवादी देशों के आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप इन देशों तथा बाहर के मजदूर वर्ग पर हर ओर से हमला हो रहा है। उद्योगपति बड़े पैमाने पर छंटनी व वेतन कटौतियों के माध्यम से यह दबाव मजदूर वर्ग पर डाल देना चाहते हैं साथ ही बढ़ी मुद्रास्फीति से लाभ की अवस्था बनाए रखना चाहते हैं ताकि विश्व बाजार व आर्थिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त होने से बचाया जा सके। वे विश्व-बाजार की एकीकृत करना चाहते हैं ताकि बड़े से बड़े झटके को सहन करने की उसकी क्षमता बढ़े। लेकिन तथ्यों से यही संकेत मिलता है कि ये सब उपाय भविष्य में बहुत कारगर सिद्ध नहीं होंगे।

पूंजी के तीन केंद्र

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बारे में दो दशक से बातें होती रही है। लेकिन यह प्रक्रिया हाल के वर्षों में तेज हो गयी है। यूरोपीय देश निकट भविष्य में एक साझे मोनिटरी सिस्टम तथा साझी मुद्रा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। व्यापार की बाधाएं तोड दी गयी हैं तथा पूंजी व श्रम के लिए साझा बाजार तैयार किया जा रहा है। अब यूरोपीय इजारेदार और बड़े दायरे में काम करेंगे। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है, अमरीका का रवैया कनाडा व मेक्सिको को अपने साझा बाजार में मिला लेने का था। मलेशिया, सिंगापुर, थाइलैंड, इंडोनेशिया तथा दक्षिण कोरिया को मिलाकर जापान के पास पूर्वी हिस्सा ही। बल्कि भौगोलिक सामीप्य वे कारण न्यूजीलैंड भी उसके व्यापार क्षेत्र में आता है।

अपनी विश्व आधिपत्य की महात्वाकांक्षाओं को बनाए रखने की कोशिश में अमरीका प्रतिवर्ष आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा हैं। मैंने पहले ही कहा है कि अमरीका अपने साथियों पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था के एकमात्र रक्षक होने के नाम पर वह अपने साथियों से लगातार छूट हासिल करता जा रहा है। मुक्त व्यापार प्रतिस्पर्धा के नाम पर वह जापान तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों पर अमरीकी वस्तुओं के लिए अपने बाजार खोल देने के लिए दबाव डाल रहा है जबकि अपने देश में संरक्षणवादी नीतियां ही अपना रहा है। एक तरफ अमरीका मुक्त व्यापार की बात करता है तो दूसरी ओर कपड़े आदि के आयात पर रोक लगाने के लिए कोटा-प्रणाली पर अमल कर रहा है। लेकिन इन संरक्षणवादी नीतियों के बावजूद अमरीका पर जापानी व्यापारिक दबाव बढ़ रहा है।

दक्षिण-पूर्व एशिया तथा आस्ट्रेलिया की राष्ट्रपति बुश की हाल की यात्रा, जिसमें अमरीकी उद्योगपति भी उनके साथ थे, उन देशों पर अमरीकी वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोलने के लिए दबाव डालने के लिए थी। आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी अमरीका के इस दोहरे रवैये की आलोचना की। जापान में राष्ट्रपति बुश को जापानी किसानों के विरोध-प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। वे अमरीका द्वारा जापान से सब्सिडी हटाने का आग्रह करने तथा अपने यहां सब्सिडी जारी रखने की दोहरी नीति का विरोध कर रहे थे। जापान अधिक से अधिक कुछ हजार के ऑटोमोबाइल उत्पादों का ही आयात कर सकता था। जापान की इस टिप्पणी ने आग में घी का काम किया है कि अमरीकी उद्योगपति पिछड़े हुए हैं क्योंकि अमरीकी मजदूर अनपढ़ हैं। जापानी प्रधानमंत्री का कहना था कि अमरीका में प्रतिभाएं उत्पादन के क्षेत्र में आने के बजाय वाल-स्ट्रीट (शेयर बाजार) में ही खप जाती हैं।

अमरीकी मजदूर जापानी आयात के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। उसके गुस्से को जातिवाद की ओर मोड़ा जा रहा है। ऐसी ही प्रवृत्ति यूरोप में नजर आ रही है। तीसरी दुनिया के अप्रवासी मजदूरों पर गलियों में हमले किये जा रहे हैं।

विश्व-व्यापी साझा बाजार स्थापित करने की कोशिश से देशों की परंपरागत सीमाओं पर तनाव पैदा हो रहा है। विभिन्न साम्राज्यवादी देशों के व्यापारिक हितों के बीच टकराव पैदा हो रहा है।

तृतीय विश्व तथा नयी विश्व-व्यवस्था

सोवियत संघ के विघटन के बाद तीसरी दुनिया के देशों की स्थिति और कमजोर हो गयी है। हालांकि साम्राज्यवादी देशों में आर्थिक मतभेद बरकरार हैं लेकिन वे अपना बोझ तृतीय-विश्व के देशों पर डालने के मामले में एकमत हैं। दरअसल जी-7, जी-22 तथा ओ.ई.सी.डी. आदि विश्व बैंक व मुद्राकोष की मदद से तीसरी दुनिया के लिए पुनः उपनिवेशवादी योजना योजना बनाने में जुटे हैं। विश्व बैंकों की कठोर शर्तों व असमान व्यापार प्रतिबंधों के माध्यम से वे अपना बोझ तीसरी दुनिया पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक ब्लैकमेल द्वारा वे अरब लीग, अफ्रीकी एकता के स्थानीय संगठनों को कमजोर करने के प्रयास कर रहे हैं।

तीसरी दुनिया के देश जो अभी तक उपनिवेशवादी परिस्थितियों से राहत नहीं पा सके हैं इन साम्राज्यवादी दबावों का शिकार बनाये जा रहे हैं। उनके ऊपर 1500 बिलियन डालर के कर्ज का दबाव बढ़ रहा है जो उन्हें साम्राज्यवादी देशों अथवा फंड-बैंक को देना है। अधिकतर देशों की कमाई हुई विदेशी मुद्रा का 50 प्रतिशत कर्ज चुकाने में चला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था (आई.एम.ई.ओ.) में जिसका संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुझाव दिया था; आपसी विश्वास तथा एक-दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए संसाधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों को हस्तांतरित किए जाने की बात कही गयी थी लेकिन अमरीका तथा उसके साम्राज्यवादी साथियों द्वारा सुझायी गयी नयी विश्व व्यवस्था उपर्युक्त अवधारणाओं के ठीक विपरीत है। प्रमुख उद्देश्य साम्राज्यवाद की दादागिरी कायम करना है। 'बैंक फंड' का इस्तेमाल तीसरी दुनिया के देशों को जाल में फंसाने के लिए किया जा रहा है। विकसित देशों के संसाधनों को अविकसित देशों को सौंपने के विचार को असमान व्यापार प्रतिस्पर्धा द्वारा बदल दिया गया है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी देश विश्व बैंक से तब तक ऋण नहीं ले सकता जब तक कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य न हो। मुद्रा कोष की नीतियां विकसित देशों द्वारा निर्धारित की गयी हैं। मुद्रा कोष में अमरीका का विशिष्ट स्थान है। तीसरी दुनिया पर अवमूल्यन, व्यापार, विदेशी मुद्रा का स्वागत तथा सब्सिडी वापस लेने की शर्तें थोपी जाती हैं। ये शर्तें मुद्रा कोष के प्रभावशाली सदस्य देशों के हितों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। मुद्रा कोष में फैसला करने का एक कोटा व्यवस्था पर आधारित है जिसके द्वारा प्रत्येक देश की वोट देने की क्षमता निर्धारित होती है। जिन देशों ने मुद्रा कोष से ऋण लिया है वे उन समस्याओं से नहीं उबर सकते जिनका वे सामना कर रहे हैं। 1981 में जब भारत ने आई एम एफ से ऋण लिया था उस समय जो उम्मीदें जाहिर की गयी थीं वे पूरी तरह गलत साबित हो गयी हैं। ऐसा ही ब्राजील, चिली, पेरु, बोलिविया, जमैका, फिलीपीन, सोमलिया, सूडान, तंजानिया, लेसोथो व घाना आदि देशों में हुआ है। इनमें कुछ कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। मुद्रा कोष का उद्देश्य तीसरी दुनिया के देशों की समस्याओं का समाधान करना नहीं है। इसका कामकाज विकसित पूंजीवादी देशों के हितों को ध्यान में रखकर होता है।

हाल ही में प्रो. चोसुडोवस्की द्वारा 72 ऐसे देशों के अध्यक्ष से, जिन्होंने मुद्राकोष से ऋण लिया है, यह बात सामने आयी है कि उनमें से कोई भी देश अपने संकट से उबर नहीं पाया।

इसी प्रकार स्वयं विश्व बैंक द्वारा भी ऐसे 34 देशों पर अध्ययन किया गया। बावजूद तमाम जोड़-तोड़ के यह साबित नहीं किया जा सका कि उनमें से किसी देश को लाभ हुआ है।

सोवियत संघ के विघटन से स्वतंत्र होकर अमरीका अब सब जगह घुसपैठ करके अपनी शर्तें लागू करवाने की कोशिश कर रहा है। कुवैत की आजादी की रक्षा के नाम पर सुरक्षा परिषद का बहाना लेकर ईराक के खिलाफ जो विध्वंसक युद्ध छेड़ा गया उसका उद्देश्य भी उस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तेल प्रधान अड्डा बनाये रखना था। सोवियत संघ के ध्वस्त होने के बावजूद अमरीका विश्व भर में अपने सैनिक अड्डे बरकरार रखे हुए है। केवल फिलीपीन में जन प्रतिरोध के कारण उन्हें हटकर मलेशिया जाने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि ईराक में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं लेकिन उसे अपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति—तेल बेचने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में फिलीस्तीनी समस्या को सुलझाने के लिए वार्ता चल रही है लेकिन फिलीस्तीनी लोगों पर इजराइली हमलों को प्रोत्साहन देकर पी.एल.ओ. को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है तथा उनकी मातृभूमि की मांग को नकारा जा रहा है।

अब लीबिया पर भी सुरक्षा परिषद की इजाजत से अमरीकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। उनसे, कहा जा रहा है कि वे उन दो लीबियाई नागरिकों को अमरीका को सौंप दें जिनके ऊपर अमरीका ने हवाई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की स्थिति अमरीकी इरादों को पूरा करने के एक उपकरण जैसी होती जा रही है।

भारतीय सुधार

कामरेड,

भारत सरकार द्वारा विश्व-बैंक मुद्रा कोष के निर्देश पर हाल ही में लागू किये आर्थिक व ढांचागत सुधारों पर उपर्युक्त सन्दर्भ में विचार करना चाहिए। विश्व बैंक के ढांचागत सुधारों का मतलब है कर, बैंक, जन प्रतिष्ठान, कृषि आदि क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन। ये सब देश की प्रभुसत्ता पर हमला है। जिस प्रकार सत्ता में आते ही नरसिम्हा राव सरकार ने जल्दबाजी में ये सब शर्तें मंजूर की हैं उससे यही साबित होता है। सरकार को 11 नवम्बर 1991 को शर्तों से संबंधित विश्व बैंक को लिखा गया पत्र संसद में पेश करने पर मजबूर किया गया। उससे साबित होता है कि सरकार ने शर्तों को स्वीकार करने से पहले संसद को विश्वास में लेना आवश्यक नहीं समझा तथा इन शर्तों को स्वीकार कर लेने के बाद सरकार के पास अपने विवेक से काम करने की आजादी भी नहीं रह जाती। यह देश की सत्ता के साथ समझौता है। नरसिम्हाराव द्वारा इस बात से इंकार करना किसी को मूर्ख नहीं बना सकता।

मजदूर वर्ग द्वारा इन नीतियों का विरोध 29 नवंबर की अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल से स्पष्ट हो गया, जो कि भारतीय श्रम आन्दोलन के हाल के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। हड़ताल इतनी व्यापक थी कि उसके आयोजक भी चकित रह गये थे। सरकार द्वारा उस चेतावनी को नजरअंदाज ही नहीं किया जा रहा बल्कि वे विश्व बैंक की शर्तों को लागू करने का प्रयास कर रही है। यहां पर मैं इन शर्तों के विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन रोजगार व अन्य क्षेत्रों में इन नीतियों से होने वाले असर के बारे में अवश्य बताना चाहता हूँ।

अर्थव्यवस्था को व्यापक बनाने के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि वित्तीय क्षेत्रों जैसे बैंक व बीमा आदि में भी खुलकर खेलने की छूट दी जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को 100 प्रतिशत इक्विटी तथा विद्युत क्षेत्रों में 16 प्रतिशत लाभ के वायदे पर देश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी इक्विटी अनुपात में ढील दी गयी है। विश्व की अनेक विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे जनरल मोटर्स को भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अपने यहां घाटे का सामना कर रही हैं भारत में उदार स्थितियों का लाभ उठाने के लिए यहाँ उद्योग शुरू करने जा रही हैं। इस संदर्भ में हमें हाल की विदेश यात्रा के दौरान अमरीकी उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री के आश्वासन पर ध्यान देना चाहिए कि 'अब और राष्ट्रीयकरण नहीं होगा।' बड़े इजारेदार घराने पहले से ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझे में उद्योग लगाने को तैयार हैं जबकि उनके घाटे में चल रहे उद्योग बन्द हो रहे हैं। बैंक व बीमा क्षेत्रों में देशी तथा विदेशी निजी कंपनियों को काम करने की छूट दी जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय पुनर्वास कोष की स्थापना करके समापन नीति लागू करने का फैसला कर लिया है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सुधारों के परिणाम अब सामने आ रहे हैं। 98 तथाकथित बीमार सरकारी इकाइयों में कार्यरत 8 लाख मजदूरों का रोजगार खतरे में है। सरकार ने हाल ही में ढांचागत सुधारों के नाम पर विभिन्न सरकारी विभागों में 10 प्रतिशत स्टाफ कम करनेके निर्देश दिए जा रहे हैं। निजीकरण के साथ ही साथ मशीनीकरण व आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। जिससे लाखों मजदूरों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नरसिम्हा समिति के विचार से बैंक उद्योग में 3 लाख कर्मचारी फालतू हैं, भारतीय रेल में वर्तमान 16 लाख स्टाफ को घटाकर 4 लाख करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा रेलवे में भर्ती भी पिछले 3-4 वर्षों से बन्द है। आंशिक निजीकरण भी किया जा रहा है। चूंकि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रामीण रोजगार जैसी विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए अनुदान नहीं दे रही है अतः अनेक लोग फालतू हो गये हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हर तरफ से हमला हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में लाखों लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, इस प्रकार कुल रोजगार क्षमता में व्यापक कमी होने जा रही है।

विदेशी कम्पनियों को भारत में उद्योग लगाने का खुला आमंत्रण देने से देश के वर्तमान उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर विद्युत क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को 100 प्रतिशत इक्विटी तथा 16 प्रतिशत लाभ ले जाने की अनुमति दी गयी है। उन्हें बाहर से अपनी मशीनें लाने की इजाजत दी गयी है। विद्युत दरें तीन से चार गुना बढ़ा दी जायेंगी तथा अनेक भारतीय उद्योग बिजली की बढ़ी हुई दरों के कारण बन्द हो जायेंगे। इससे हमारे कृषि क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान कृषि क्षेत्र को विद्युत दरों में जो छूट दी जा रही है वह बन्द कर दी जायेगी तथा इसका अर्थ है कि हमारा कृषि उद्योग मृत हो जायेगा। इससे हमारे कृषि उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। हमारी औद्योगिक उत्पाद महँगे हो जायेंगे तथा उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता घट जायेगी। हमें अन्न के मामले में भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ेगा जिनके मामले में हम आज 'आत्म-निर्भर' हैं। बी. एच ई. एल. व अन्य क्षेत्रों में हमारी प्रमाणित क्षमता बेकार चली जायेगी। जब सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का पुनर्गठन व निजीकरण किया जायेगा तो हमारे बहुत से कुशल व प्रशिक्षित कर्मचारी जैसे प्रबंधक, तकनीशियन आदि फालतू हो जायेंगे। संक्षेप में स्वतंत्रता-पूर्व की-सी स्थिति पैदा होने जा रही है।

रोजगार

सरकार की इन नीतियों से रोजगार क्षमताएं तेजी से कम होने जा रही हैं। वर्तमान में कुल पंजीकृत बेरोजगार 3.40 करोड़ बताये जाते हैं। बीमार उद्योगों की सूची 4 लाख तक पहुंच गयी है। परिणामस्वरूप लाखों लोगों का रोजगार छिन जायेगा। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अनुमानित बेरोजगारी सात करोड़ थी। इस सूची में हमें लाखों और नाम भी जोड़ने हैं जो हमारे विश्व-बैंक मुद्रा कोष की शर्तों पर चलने के फलस्वरूप बेरोजगार हो जायेंगे।

रोजगार संबंधी स्थिति पर 11 मार्च 1992 के एल. सी. जैन के लेख में प्रकाश डाला गया है जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। बेरोजगारी के बारे में चुप्पी साधे रहने के लिए वित्त-मंत्री की आलोचना करने के बाद लेख में कहा गया है कि : "वित्तमंत्री को रोजगार की खतरनाक स्थिति का भी उल्लेख करना चाहिए था। 1978 से 1988 के बीच रोजगार विकास दर 2.8 प्रतिशत से घटकर 1.3 प्रतिशत हो गयी। यह दर श्रम शक्ति की विकास दर से आधी है। उत्पादन में 4.7 से 7.2 गिरावट हुई है। और यह सब ऐसे समय में, जब अर्थव्यवस्था की विकास दर सकल घरेलू उत्पादन के 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो रही थी। इस अवधि में उत्पादन बढ़ा है। लाभ बढ़ा है। शेयर बाजार में उछाल आया है। केवल रोजगार घटा है। इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया ने अपने आप को मजदूर की 'गिरफ्त' से मुक्त कर लिया है।

नयी नीतियों के प्रभाव से रोजगार के अवसर घटेंगे। नरसिम्हा राव सरकार मजदूरों का भोजन और रोजगार से मुक्ति दे रही है। और अन्ततः जीवन से भी मुक्ति हो जायेगी। लेकिन देशी और विदेशी इजारेदारों के लिए लाभ बढ़ रहा है।"

आम लोगों के लिए केवल मूल्य-वृद्धि और तंगहाली है। देश के लिए स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता के नाम पर समझौता है।

बजट के ठीक पहले संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नयी नीतियां लागू करने से पहले भारत सरकार द्वारा किए गये दावे बिल्कुल गलत साबित हुए हैं।

टेबल-1

(पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत परिवर्तन)

	1988-89	1989-90	1990-91(पी.)	1991-92(पी.)
सकल राष्ट्रीय उत्पादन	10.5	6.1	5.8	2.5 से 3
सकल घरेलू उत्पादन	10.5	6.0	5.6	2.5 से 3
कृषि उत्पादन	21.0	2.1	2.6	0.0☆
अन्न उत्पादन	21.0	0.6	3.0	1.5
औद्योगिक उत्पाद	8.7	8.6	8.5	0.8
थोक मूल्य सूचकांक	5.7	9.1	12.1	11.8
औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2.5	6 6	13.6	13.1
वर्तमान दर पर निर्यात (रुपयों में)	29.1	36.8	17.6	28.1
वर्तमान दर पर निर्यात (अमरीकी डॉलर में)	15.6	19.0	9.1	5.0

☆ अनुमानित (पी.) प्रोविजनल

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार की निवेश घटाने व 23 प्रतिशत अवमूल्यन की नीति से हमारे औद्योगिक विकास में मदद नहीं मिली है और विश्व में घाटे के रुझान के कारण हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। संक्षेप में पिछले बजट श्री मनमोहन सिंह द्वारा किए गए सभी दावे गलत साबित हो गये हैं तथा उनका यह दावा कि अगले वर्ष तक सब ठीक हो जायेगा, गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।

आज हम पाते हैं कि मजदूरों के सभी तबके इन उपायों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हाल ही में सरकारी क्षेत्र की यूनियनों, केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों तथा केन्द्र सरकार के विभागीय प्रतिष्ठानों की 5-6 मार्च को कलकत्ता में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में अप्रैल 1992 के अन्तिम सप्ताह में अखिल भारतीय हड़ताल का फैसला किया गया। इससे मजदूरों के मूड के बारे में पता चलता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेवर लोगों का तबका भी सरकारी नीतियों के प्रति गुस्से में है सिर्फ इसीलिए नहीं कि इससे रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे बल्कि इसलिए भी इनमें देश की स्वाधीनता व प्रभुसत्ता पर समझौता

किया गया है। अब पेशेवर लोग विशेषकर अधिकारी व तकनीशियन इस नीति के खिलाफ अपने आप को संगठित कर रहे हैं। रेलवे की क्षमताओं में कटौती करने के खिलाफ रेलवे के प्रथम श्रेणी के अधिकारी सरकार के खिलाफ युद्ध के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। वे काले बिल्ले पहन कर विरोध दिवस मना रहे है। बैंक के अधिकारी व कर्मचारी मिल कर नरसिम्हा समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आई. डी. बी. आई. के अधिशासी निदेशक तक के स्तर के अधिकारियों ने संगठन को समाप्त करने व उसके निजीकरण के खिलाफ एक दिन का विरोध कार्यक्रम आयोजित किया। कामरेड, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अब सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के अधिकारी भी अपने हितों तथा देश की प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष में हमारे साथ आ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अतः स्थितियां इस बात की मांग करती हैं कि जनता के साथ मिलकर सरकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर वर्ग नेतृत्वकारी भूमिका निभाए।

श्रम संगठनों का कन्फेडरेशन

कॉमरेड, जानते हैं कि हमारे चौथे, पांचवे तथा छठे सम्मेलन में कॉ. बी. टी. आर. श्रम संघों का परिसंघ बनाने का विचार रख रहे थे। वे सरकार की जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी तथा पतनोन्मुख नीतियों के खिलाफ संघर्ष करके उन्हें बदलवाने के लिए श्रम संगठनों के एक केन्द्रीय विरोध मंच का सुझाव दे रहे थे।

11-15 अप्रैल, 1979 को मद्रास में हुए चौथे सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि—

"सीटू सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों, कर्मचारी संघों, केन्द्रीय व राज्य सरकारों के कर्मचारियों व अध्यापकों व प्राध्यापकों से मांग करती है कि वे सभी वर्गों के हितों की रक्षा व साझा श्रम नीति के लिए संगठित होकर आगे आने की मांग करती है···

"हमारी इच्छा है कि वे सभी संघठन तुरन्त स्थिति का सामना करने के लिए आगे आएं तथा समान मांगों के लिए संघर्ष करके यह बता दें कि मजदूर आंदोलन एक व अविभाजित है···

"क्या हम 'परिसंघ' जैसे हल्के ढांचे अथवा समन्वय समिति के तहत एक नहीं हो सकते ताकि सर्वसम्मत फैसले लिए जा सकें। यह ऐसा समय नहीं है कि एकता के इस अस्थायी आधार को छोड़ दें तथा संगठित हों जब हम पर हमला हो।

"यदि श्रम संगठनों को मजदूर-हितों की रक्षा करनी है तो सरकार की आयात-निर्यात नीतियों पर उनकी एक साझा नीति होना आवश्यक है। सम्मिलित तथा सतत् प्रयास के बिना नीतियों के लिए संघर्ष नहीं किया जा सकता।"

कानपुर में हुए हमारे पांचवें सम्मेलन (13-17 अप्रैल 1983), में उन्होंने उल्लेख किया था :

"अपने पिछले सम्मेलन में सीटू ने विचारों के आदान-प्रदान के उद्देश्य से श्रम संगठनों के परिसंघ के रूप में एक साझा मंच का आह्वान किया था···

"आर्थिक स्थिति तथा बेरोजगारी व कुशल प्रबंधन जैसे मुद्दों की एक रूप रेखा हमारी एकता तथा लोगों में विश्वास पैदा करने में काफी सहायक होगी···

"श्रम संगठनों को आर्थिक तथा औद्योगिक मामलों को सुलझाने में बराबरी के स्तर पर सहयोग करने की इच्छा भी प्रकट करनी चाहिए। उन्हें ऐसी इच्छा जनता के बीच जाहिर करनी चाहिए तथा स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह सरकार तथा शासक वर्ग ही है जो मजदूर वर्ग को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोकता है।

बम्बई में 18-22 मई 1980 को हुए छठे सम्मेलन में पुनः उन्होंने स्पष्ट किया :

"अपने संगठित प्रयासों से हम वह शक्ति पैदा कर सकते हैं जिसका सरकार व शासक वर्ग सम्मान करे। हम श्रम संगठनों के इस उद्देश्य को हासिल करने में अभी बहुत पीछे हैं। अतः हमें अपनी वर्तमान कमियों को दूर करने तथा श्रमिक आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए······" सीटू ने बहुत श्रम संगठनों के एक परिसंघ का सुझाव रखा था जिसमें मजदूर संबंधी मामलों पर विचार किया जा सके तथा सर्वसम्मत फैसले लिए जा सकें। आज समय है कि हम अपने इस सुझाव को दोहराएं तथा उस पर जोर दें। राष्ट्रीय प्रचार समिति के विस्तार तथा पुनर्गठन व सभी श्रम संगठनों को एक परिसंघ के अन्तर्गत लाने के लिए प्रयास नितांत आवश्यक हैं, न केवल अपने हितों की रक्षा के लिए देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए भी। कर्मचारियों व मजदूरों की ओर लगातार जन-प्रतिरोध के चिन्ह देखने में आ रहे हैं। यदि इस बढ़ते हुए असंतोष देने के अपने प्राथमिक कर्त्तव्य को श्रम संगठन पूरा करते हैं तो सम्पूर्ण भारतवर्ष के मजदूर वर्ग द्वारा एक संगठित आंदोलन की संभावनायें बन रही हैं। *सीटू को इस महान एकता के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने चाहिए क्योंकि उसी प्रकार हम राष्ट्रविरोधी, विघटनकारी ताकतों तथा सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर सकते हैं और राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत कर सकते हैं।*

आज की स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है। सरकार पहले ही विश्व बैंक मुद्रा कोष के दबाव के आगे झुक गयी है और उसने वे नीतियाँ लागू करना शुरू कर दिया है जो देश की स्वतंतता व प्रभुसत्ता से समझौता है। हमने पिछले 40 सालों में जो कुछ अर्जित किया है वह सब नष्ट होने जा रहा है।

इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सरकार की विदेश नीति में हाल में आए बदलाव हैं, विश्व बैंक व मुद्राकोष के दबाव में सरकार अमरीका के सामने झुक गयी है तथा अमरीका के साथ संयुक्त सैनिक अभ्यास के लिए तैयार हो गयी है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। प्रत्येक भारतीय को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम अमरीकी स्वार्थों का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और

[शेष पृष्ठ 10 पर]

की समस्याओं को किसी प्रकार, राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत नीतियों को उलटने का बहाना नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने भी ऐसे अनेक देशों की मिसालें दीं, जिन्होंने अपने यहां बहुराष्ट्रीय निगमों का खुली छूट देकर अपनी मनमर्जी करने का मोका दिया था।

अर्थशास्त्री कमल नारायण काबरा ने भारत जैसी पिछड़ी व्यवस्थाओं में बहुराष्ट्रीय निगमों की घुसपैठ के निहितार्थों और उसके संभव राजनीतिक परिणामों की ओर ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि तमाम सुधारों की मुख्य दिशा बैंकिंग के निजीकरण की है।

विश्व ट्रेड यूनियन फेडरेशन के देव कुमार गांगुली ने बैंक कर्मचारियों के जायज संघर्ष के लिये समर्थन का भरोसा दिलाया। सांसदगण चित्त बसु, सुकोमल सेन व गुरुदास दासगुप्त; यू टी यू सी नेता अबनी राय, सर्वोच्च न्यायालय के वकील आर के गर्ग आदि ने भी कन्वेंशन को सम्बोधित किया। इनमें से हरेक वक्ता ने बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण का और वित्तीय क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय निगमों की लूट के लिये खोले जाने का विरोध किया।

आशीष सेन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। प्रस्ताव में नरसिम्हन कमेटी की सिफारिशों से निकलने वाली बुराइयों को रेखांकित करते हुए सरकार से आग्रह किया गया कि इन्हें लागू करने से बाज आये। प्रस्ताव में सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों से अपील की गयी है जि जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती है, इन कोशिशों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखें।

राष्ट्रीय कन्वेंशन का समापन, विश्वास के स्वर के साथ हुआ। नरसिम्हन की सिफारिशें स्वीकार नहीं की जायेंगी के साथ कन्वेंशन का समापन हुआ।

१९९२-९३ के बजट के खिलाफ प्रदर्शन के लिए सीटू का आह्वान

डॉ. मनमोहनसिंह द्वारा पेश किए गए बजट का उद्देश्य विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को दिये गये वादों को पूरा करना था न कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना अथवा मेहनतकश तबके के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। स्टील, सीमेंट, कपड़ा, घड़ियों तथा दुपहिया वाहनों पर बढ़ाये गए करों से मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना कब्जा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन क्षेत्रों में कस्टम ड्यूटी कम करवाना चाहती थीं वहां यह घटा दी गयी है।

बजट घाटे को मुद्राकोष द्वारा सुझाये गये स्तर तक सीमित रखा गया है तथा इसके लिए अनेक कल्याण योजनाओं, रोजगार पैदा करने, ग्रामीण विकास आदि में कमी लायी गयी है तथा सब्सिडी घटा दी गयी है। यह बजट सार्वजनिक क्षेत्र के खात्मे की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास को अलविदा कहता है। इससे बड़े उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रसन्नता होगी जबकि मजदूर वर्ग का जीवन-स्तर और नीचे चला जायेगा।

बजट की आयकर सीमा 28,000 रु. तक मामूली रूप से बढ़ाया गया है जबकि उच्च आय के स्तर पर अधिक छूटें दी गयीं हैं। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। यह आम जनता को आघात पहुंचाता है जबकि कर चोरों, काला बाजारी करने वालों व जमींदारों को प्रसन्नता हुई है।

सीटू सभी श्रम संगठनों व मजदूर वर्ग से मांग करती है कि 4 मार्च को केन्द्रीय बजट के खिलाफ तथा मूल्य-वृद्धि, निजीकरण, बजट प्रावधानों तथा भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ 9 मार्च, 1992 को फैक्ट्रियां व अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रर्शन करें।

[पृष्ठ 8 का शेष]

कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक गंभीर बात बात है।

प्रेस द्वारा पता चला है कि सरकार फालतू चावल क्यूबा को न बेचने तथा अमरीका से 2 लाख टन गेहूं आयात करने को राजी हो गयी है। अमरीका भारत को अपने मित्र देशों को थोड़ा-सा चावल बेचने को रोक रहा है। भारत व क्यूबा स्वतंत्र देश हैं। दोनों आपस में किसी भी तरह का व्यापार, बिना कानूनी अड़चन के कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अमरीका के समक्ष समर्पण कर दिया। इससे पता चलता है कि भारत की स्वाधीनता के साथ समझौता किया जा रहा है।

राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहा था कि "यदि हम वर्तमान संकट से उबरना चाहते हैं तो हमें स्वेच्छा से दो वर्ष के लिए हर तरह की हड़ताल, बन्द, काम रोको आदि को बन्द कर देना चाहिये। यह सपने बच्चों तथा आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। हालांकि राष्ट्रपति ने ये अधिकार स्वेच्छा से छोड़ने की बात कही थी लेकिन सरकार जबर्दस्ती हड़ताल का हक छीन रही हहै, जैसे कि अस्पतालों व शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों से हड़ताल का अधिकार छीनने से जाहिर होता है। वे औद्योगिक विवाद कानून में परिवर्तन करके छंटनी व मिलबन्दी में आने वाली बाधाओं को भी दूर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमें सरकार के वित्त सलाहकार श्री अशोक देसाई की बात पर भी ध्यान देना चाहिए— "स्थायी रोजगार नहीं होना चाहिए।" इससे उद्योगों के विकास में बाधा आती है। अतः, कामरेड, स्थिति हमारे छठे सम्मेलन के समय से और ज्यादा गंभीर हो गयी है।

अतः में आपसे संयुक्त परिसंघ के सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह एक अत्यन्त आवश्यक कार्य है।

अन्त में मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीटू की जिम्मेदारियां बढ़ गयी हैं उसे मजदूर व राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए होने वाले संघर्ष का नेतृत्व करना है।

सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग,
नागपुर, 13-15 मार्च, 1992

सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान

पी. के. गांगुली

13-15 मार्च को नागपुर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग ने 5-6 मार्च को हुए अखिल भारतीय सम्मेलन के फैसलों की पुष्टि की तथा सीटू की यूनियनों से सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ अप्रैल के अन्त में एक राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल की तैयारी करने की अपील की।

सरकार द्वारा विश्व बैंक व मुद्रा कोष के निर्देश पर तैयार की गयी आर्थिक नीतियों को तेजी से लागू करने जाने के संदर्भ में हुई इस बैठक में अप्रैल के अन्त में अखिल-भारतीय हड़ताल के लिए सदस्यों की पूरी तैयारी दृष्टिगोचर हुई।

हड़ताल की अपील पर चर्चा की शुरूआत कॉ० ई० बालानन्दन ने अपने अध्यक्षीय भाषण में की। उन्होंने सभी विकसित पूंजीवादी देशों में मिलबन्दी, बेरोजगारी, छंटनी तथा मुद्रास्फीति आदि की गंभीर स्थिति की ओर इशारा किया तथा बताया कि ये देश अपने संकट का बोझ तीसरी दुनिया के देशों पर डालना चाहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद वर्ग संतुलन को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हुए अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवादी देश भारत की आर्थिक व औद्योगिक नीतियों को अपने हितों के अनुरूप ढालना चाहते हैं। वर्तमान आर्थिक नीतियां नरसिम्हा राव सरकार द्वारा विश्व बैंक व मुद्रा कोष की मांगों के समक्ष समर्पण का नतीजा है। इन्हीं नीतियों के खिलाफ 29 नवम्बर की हड़ताल की गयी थी। अब सरकार ने मुद्रा कोष की देख रेख में इन नीतियों को लागू करना आरंभ कर दिया है तथा मजदूरों को वह इस झूठे भुलावे में रख रही है कि मिलबन्दी या छंटनी नहीं होगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि विश्व बैंक तथा मुद्रा कोष के दबाव में सरकार विकसित हो रहे मजदूर आन्दोलन की गतिविधियों को सीमित करने के लिए श्रम कानूनों में भी परिवर्तन करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी चुनौतियों का एक मात्र उत्तर हड़ताल है।

सभी विकसित पूंजीवादी देशों के संकट के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका, जो कि पूंजीवादी विश्व व्यवस्था का अगुआ था, विश्व का सबसे बड़ा कर्जदार देश है। अमरीका पर 360,000 करोड़ डॉलर का अनुमानित विदेशी कर्ज है तथा साथी औद्योगिक देशों के साथ व्यापारिक मतभेदों के कारण यह और बढ़ रहा है। ईराक पर उसकी तथाकथित विजय के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं है। उसे ऑटोमोबाइल उद्योग, स्टील उद्योग, आई. बी. एम. कम्प्यूटर्स, तथा बैंक आदि उद्योगों में घाटा उठाना पड़ रहा है। मिलबन्दी के बाद दसियों हजारों मजदूरों की छंटनी हुई है। मंदी अमरीकी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता बन गयी है और बेरोजगारी लगभग 10% बढ़ गयी है। उन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली तथा जापान की भी ऐसी ही तस्वीर सामने रखी।

उन्होंने कहा कि 'पांच के समूह' अथवा '22 के समूह' का कोई भी पूंजीवादी देश ऐसा नहीं है जो इस सतत् मन्दी की समस्या से घिरा न हो। यह रुझान तीस के दशक की आर्थिक मंदी जैसा रूप लेने की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इस तथ्य की ओर भी इशारा किया कि तत्कालीन समाजवादी देशों ने बाजार व्यवस्था का जिस उत्साह के साथ स्वागत किया था वह बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मिल बन्दी तथा आवश्यक वस्तुओं की कमी जैसी कठोर वास्तविकताओं के आगे ठंडा पड़ता जा रहा है।

उन्होंने समाजवाद की महान उपलब्धियों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा कहा वर्तमान दौर अस्थायी है जो कि समाजवाद के निर्माण के दौर में हुई गलतियों का परिणाम हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम सबके सामने है। अमरीका का दबदबा केवल उसकी सैनिक क्षमता के कारण बना हुआ था। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की व्यवस्था में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर अमरीका भारत पर अवमूल्यन, मुक्त उद्योग व व्यापार नीति, विदेशी पूंजी के साथ रियायती व्यवहार तथा सब्सिडी घटाने की शर्तें थोप रहा है। इसके अतिरिक्त जी. ए. टी. टी. मंच तथा अपने श्रम कानूनों का दुरुपयोग करके भारत की आर्थिक संप्रभुता को नष्ट करके उसको अपने नव उपनिवेशवादी जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है।

संगठित मजदूर आन्दोलन के विकास तथा इंटक व बी. एम. एस. द्वारा कलकत्ता सम्मेलन में भाग लेने का विश्लेषण करते हुए उन्होंने तत्कालीन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि मुद्रा कोष के निर्देश पर सरकार द्वारा बनायी गयी आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप देश स्वतंत्रता, संप्रभुता व अर्थव्यवस्था के लिए उत्पन्न खतरे से उनकी रक्षा करने के लिए श्रम संगठनों का एक राष्ट्रीय परिसंघ बनाने के कॉ. बी. टी. आर. के आह्वान को दोहराया।

अध्यक्ष के आह्वान को बल प्रदान करते हुए उद्घाटन सत्र में ही एक प्रस्ताव सीटू के महासचिव कॉ. एम. के. पंधे द्वारा रखा गया जिसका समर्थन कॉ. आर. उमानाथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने किया। प्रस्ताव सरकार की आर्थिक नीतियां, उनके कार्यान्वयन के प्रयास तथा विशेष रूप से 49 प्रतिशत तक अनिवेश से सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने के प्रयास, 98 इकाईयों को बी. आई. एफ. आर. को सौंपना, रेलवे तथा आम बजट का विश्लेषण करते हुए दूसरी राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल की पूरी तैयारी की अपील की गयी। प्रस्ताव में सभी केन्द्रीय श्रम

संगठनों से तारीख निश्चित करने की अपील की गयी तथा किसानों, युवाओं, छात्रों व महिलाओं के सभी संगठनों से भी अपील की गयी कि वे भी हड़ताल में सहयोग करें।

कॉ. एम. के. पंधे, महासचिव द्वारा रखी गयी रिपोर्ट में सरकारी नीतियों के कार्यान्वियन से उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति पर तथा आगामी पड़ताल के माहौल के बारे में विचार किया गया। कॉ. पंधे ने 29 नवम्बर की हड़ताल का लेखा-जोखा रखा तथा सरकारी नीतियों के कार्यान्वियन, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में अनिवेश तथा 98 इकाइयों को हिट लिस्ट में शामिल करने, बीमार उद्योग कानून पारित करने, बीमार इकाइयाँ बी. आई. एफ. आर. को सौंपने, राष्ट्रीय पुनर्वास कोष बनाने तथा निर्गम नीति आदि का विश्लेषण किया तथा सीटू यूनियनों से अपील की कि वे स्वतंत्र विरोध कार्यक्रम आयोजित करें तथा सभी श्रम संगठनों को हड़ताल के लिए लामबंद करें। कलकत्ता सम्मेलन में इंटक व बी. एम. एस. के भाग लेने के कारण इसे मजदूर एकता की ओर एक बड़ा कदम बताते हुए इसकी सराहना की। सरकारी व निजी उद्योगों में संगठित क्षेत्रों के मजदूरों को लामबद्ध करने के अलावा उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों व महिलाओं को साथ लेने के लिए विशेष प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने डंकल मसौदे के बारे में बताया कि यह भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता को नष्ट करने का एक खतरनाक प्रयास है। साथ ही उन्होंने अमरीकी व्यापार कानूनों सुपर-301 तथा स्पेशल 301 के बारे में कहा कि ये भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास हैं। इन सभी जघन्य साम्राज्यवादी चालों के बाद उन्होंने विशेष त्रिपक्षीय समिति में श्रम संगठनों से विचार-विमर्श के ढोंग का खुलासा करते हुए उसकी भर्त्सना की तथा हड़ताल की तैयारी करने को कहा। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने सदस्यों से सदस्यता व लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के माध्यम से संगठनों को मजबूत बनाने तथा केन्द्रीय नेतृत्व व कार्यकर्ताओं से गहरा तालमेल बनाये रखने की अपील की। संगठन की तैयारी पर और विस्तार से विचार करने के लिए रिपोर्ट में वर्ष के अन्त के पहले एक विशेष जनरल काउंसिल आयोजित करने की सलाह दी गयी। इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए केन्द्र (सीटू) एक प्रश्नावली तैयार करके विभिन्न राज्य समितियों व औद्योगिक संघों को वितरित कर देगा।

विभिन्न राज्यों से आये 42 सदस्यों के अतिरिक्त औद्योगिक फेडरेशनों से कुछ विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भी रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया। सदस्यों ने 29 नवम्बर की हड़ताल की सफलता इसके माध्यम से मजदूर एकता के अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने विभिन्न उद्योगों जैसे स्टील, कोयला, उर्वरक, तेल, टेलीकम्युनिकेशन, ऊर्जा, परिवहन, कपड़ा, रेलवे, आदि में अपनाये जा रहे पतनोन्मुख व दमनकारी रवैये के बारे में बताया। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश व अन्य राज्यों से आये सदस्यों ने पारंपरिक लघु उद्योग जैसे काजू, रेशे व हैंडलूम आदि के सरकारी नीतियों के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच जाने के बारे में बताया। अनेक इकाईयां विशेष रूप से लघु व माध्यम स्तर की इकाईयां बन्द हो चुकी हैं। अनेक सदस्यों ने मूल्य वृद्धि तथा जन वितरण प्रणाली को नष्ट किए जाने के बारे में विचार किया। उन्होंने संगठनात्मक मुद्दों पर भी अपनी राय दी तथा कहा कि संगठन को अखिल भारतीय केन्द्र से लेकर यूनियनों के स्तर तक मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने श्रम संगठनों की एकता को और मजबूत बनाने के लिए एक राष्ट्रीय परिसंघ बनाने की अपील की ताकि वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया जा सके व सरकार को वर्तमान आर्थिक नीतियां वापस लेनी पड़ें। श्रम संगठनों द्वारा एक वैकल्पिक नीति तैयार किए जाने का भी सुझाव दिया गया।

नयी तकनीक के प्रश्न पर से अलग से विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श में 14 सदस्यों ने भाग लिया। यह फैसला किया कि इस मुद्दे पर राज्यों के स्तर पर और विस्तार से विचार किया जायेगा तथा केन्द्र इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

सभी सदस्यों व नेताओं ने कलकत्ता सम्मेलन के फैसलों व उनमें इंटक व बी एम एस के भाग लेने का स्वागत किया। उन्होंने हड़ताल के लिए अपनी पूरी तैयारी की घोषणा करते हुए तारीख की जल्द घोषणा करने की मांग की। कनाई बनर्जी ने रेलवे मजदूरों के आन्दोलन के बारे में बताया।

काउंसिल की मीटिंग के एक दिन पहले कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक हुई। समिति की संयोजिका का० विमल रणदिवे ने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कामकाजी महिलाओं के संघर्षों आंगनवाड़ी महिलाओं के संगठित आन्दोलन के बारे में जानकारी दी तथा आगामी हड़ताल में महिलाओं की भागेदारी का वादा किया। का० रंजीत बसु (कोषाध्यक्ष) ने एकाउंट्स रखे जो पास हो गये। अन्त में महासचिव के जवाब के बाद हड़ताल के आह्वान के साथ रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित हो गयी। बैठक ने हड़ताल की तैयारी के तौर पर प्रायोजक समिति के आह्वान के अनुसार 2 अप्रैल को राज्य वार, क्षेत्र वार तथा उद्योग वार सम्मेलन व रैलियां आयोजित करने तथा दिल्ली में भी प्रदर्शन की अपील की।

बैठक में अन्य अनेक प्रस्ताव भी पास किये गये जिनमें, पंजाब की स्थिति, पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार, भारत पर साम्राज्यवादी दबाव, जूट मजदूरों की हड़ताल, रेल मजदूरों का संघर्ष व कावेरी जल विवाद पर प्रस्ताव शामिल थे। कई अन्य प्रस्ताव जैसे डंकल सुझाव, मूल्य-वृद्धि, त्रिपुरा तथा सांप्रदायिक व विभाजनकारी शक्तियों के बारे में प्रस्ताव सचिव मंडल को पारित करने हेतु भेज दिये गये।

15 तारीख की शाम को खुला अधिवेशन हुआ। नागपुर व आसपास के इलाकों से मजदूर इसमें भाग लेने के लिये आये। अधिवेशन की अध्यक्षता अहिल्या रांगनेकर ने की। अधिवेशन को सम्बोधित करने वालों में ई० बालानन्दन, एम के पंधे, बी पी कश्यप तथा के एल बजाज शामिल थे।

सीटू जनरल काउंसिल द्वारा पारित प्रस्ताव

शोक प्रस्ताव

13-15 मार्च 1992 को नागपुर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग उन साथियों को भारी दिल से याद करती है जो पिछली कार्यसमिति की बैठक के बाद से हमारे बीच नहीं रहे।

कॉ. आनन्दन नाम्बियार, कार्यसमिति के भूतपूर्व सदस्य, सीटू कार्यसमिति के सदस्य तथा जाने-माने मजदूर, नेता कॉ. ओ.जे.जोसेफ, जनरल काउंसिल सदस्य कॉ. ए.बी. झा, कॉ. निरंजन मुखर्जी भूतपूर्व कार्य समिति सदस्य तथा कॉ. स्वपन बोस भूतपूर्व जनरल काउंसिल के सदस्य अब हमारे बीच नहीं हैं, स्वतन्त्रता सेनानी तथा जाने-माने मजदूर नेता कॉ. ए.बी सावंत अब हमारे बीच नहीं हैं। कॉ. अब्दुला रसूल जाने-माने किसान नेता, कॉ. एम. के. कालू बिरेन गुप्ता, कॉ. जानकी अम्मा तमिलनाडु की एक प्रतिष्ठित महिला नेता व कॉ. आर.सी. सिंह, जमशेदपुर के मजदूर नेता, जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गयी, सभी हमें उस दौरान छोड़कर चले गये। उड़ीसा के कॉ. अनन्त राउत की एक संघर्ष में मृत्यु हो गयी। भाकपा के एक जाने-माने नेता कॉ. बिस्वनाथ मुखर्जी का लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया।

जनरल काउंसिल हमारे आंदोलन से जुड़े सभी दिवंगत नेता और सदस्यों को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद करती है तथा उनके अधूरे छोड़े काम को पूरा करने व लोकतांत्रिक आन्दोलन को आगे बढ़ाने की शपथ लेती है।

शहीदों को श्रद्धांजलि

13-15 मार्च 1992 को नागपुर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग पंजाब किसान सभा के नेता का. स्वर्ण सिंह चीमा तथा पांच अन्य कामरेडों के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करती है। विभाजनकारी आंदोलन के खिलाफ अपने सतत् संघर्ष के कारण खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गयी। बैठक कॉ. शंकर गुहा नियोगी की हत्या पर भी गहरा दुःख व्यक्त करती है।

जनरल काउंसिल अबोहर व संगरूर में आतंकवादियों द्वारा मारे गये शहीदों को गर्वपूर्वक याद करती है।

जनरल काउंसिल मीटिंग उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने मजदूर वर्ग तथा लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए अपनी जान कुर्बान की। काउंसिल शहीदों द्वारा दिखाई गयी हिम्मत व दृढ़ता की सराहना करती है। वे सदा मजदूर वर्ग के संघर्ष में प्रेरणा स्रोत रहेंगे।

सरकार की आर्थिक नीतियों पर प्रस्ताव

13-15 मार्च 1992 को नागपुर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग मुद्राकोष के निर्देश पर बनायी गयी आर्थिक व औद्योगिक नीतियों को वापस लेने से इन्कार करने की निन्दा करती है।

29 नवंबर को राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल व अन्य तरीकों से लगातार विरोध प्रकट करने के बावजूद सरकार देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को नजरअंदाज करते हुए मुद्रा कोष के सीधे निरीक्षण में इन नीतियों पर अमल करतीं चली जा रही है, राष्ट्रीय पुनर्वास कोष की स्थापना, बीमार उद्योग प्रावधान में परिवर्तन, निर्गम नीति, फेरा तथा एम.आर.टी.पी. को समाप्त करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त करने जैसे कदम श्रम संगठनों के सतत विरोध को नजरअंदाज करते हुए उठाये जा रहे हैं। लाभ कमा रही इकाइयों में अनिवेश को 20 से 49% तक बढ़ा कर तथा 98 बीमार इकाइयों को बन्द करने के लिए चुनकर सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र पर हमला बोल दिया है। सरकार इनमें से 58 इकाइयाँ बी.आई.एफ.आर. को सौंपने का फैसला कर चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में उठाये गये पतनोन्मुख कदमों से न केवल 4 लाख मजदूर बेरोजगारी के कगार पर पहुंच जायेंगे बल्कि देश की आर्थिक प्रभुसत्ता भी खतरे में पड़ जायेगी।

मुद्रा कोष के समक्ष पुनः समर्पण करते हुए नरसिम्हन समिति ने बैंक व सेवा क्षेत्रों में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करने की सिफारिश करी है। सार्वजनिक क्षेत्र को ध्वस्त करके तथा नरसिम्हा समिति की सिफारिशों से पूरा वित्तीय तंत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समर्पित किया जा रहा है। माल तथा यात्री बढ़ाने वाले रेल बजट तथा आम बजट में विश्व बैंक/मुद्रा कोष के निर्देशों की स्पष्ट झलक मिलती है। वित्तमंत्री द्वारा विश्व बैंक को लिखे गये पत्र के उजागर होने से यह बात स्पष्ट हो गयी है। रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई। आयात से लाइसेंस हटाने, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि, रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाने जैसे कदमों से मुद्रा स्फीति बढ़ना निश्चित है। सरकारी दर पर 40 प्रतिशत विदेशी मुद्रा से रुपये का और और दस प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन व आयात बिल में वृद्धि होगी। इस सबसे देश की भुगतान सन्तुलन की स्थिति खराब होगी।

स्वाभाविक रूप से बजट मूलतः अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है तथा सम्पत्ति कर व काले धन को नहीं छुआ गया है। स्टील, सीमेंट व कपड़े आदि पर अतिरिक्त ड्यूटी से कीमतें और बढ़ेंगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारतीय बाजार पर कब्जा करने में मदद करने के लिए कस्टम ड्यूटी घटा दी गयी है। मुद्रा कोष के निर्देश पर कल्याण कार्यक्रमों में कटौती करके, सब्सिडी घटाकर तथा ग्रामीण रोजगार, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण जैसी योज-

नाओं में कटौती करके बजट घाटे को कम में रखा गया है।

आयकर सीमा में 22,000/- रु. से 28,000/- रु. की मामूली वृद्धि एक राजनैतिक चाल है जबकि उच्च आयवर्ग को अधिक रियायतें दी गयीं हैं। बजट तथा सम्पूर्ण आर्थिक उपाय देश के मजदूर किसान व आम जनता की स्थिति को और खराब करेंगे।

इस परिस्थिति में इंटेलैक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स, निवेश संबंधी उपायों वाले डंकल सुझावों का उद्देश्य जी.ए.टी.टी. के मंच से भारत को ब्लैकमेल करना है। डंकल सुझावों की भर्त्सना करते हुए मीटिंग इनको पूरी तरह नामंजूर करने तथा ढुलमुल रवैये के लिए नरसिम्हा राव सरकार की निन्दा करती है। मुद्रा कोष के निर्देश तथा डंकल सुझाव भारत की आर्थिक प्रभुसत्ता के खिलाफ एक साजिश है।

इस पार्श्वभूमि में मीटिंग मजदूर वर्ग को उसकी 29 नवंबर की हड़ताल तथा इन नीतियों के सतत विरोध के लिए मुबारकबाद देती है। बैठक 5-6 मार्च को ट्रेडयूनियन कनवेंशन में अप्रैल के अंत में इंटक व बी एम एस सहित अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र हड़ताल के फैसले का स्वागत करती है जो मजदूर एकता की ओर एक और कदम है। बैठक सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों व फेडरेशनों से अपील करती है कि वे नयी आर्थिक व औद्योगिक नीतियों को बिना और देर किए वापस लेने की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान करें। बैठक अपनी सभी यूनियनों व राज्य समितियों से अपील करती है कि वे कलकत्ता सम्मेलन के फैसले के अनुसार देश के मजदूर आंदोलन के साथ मिलकर हड़ताल की तैयारी करें।

भारत पर बढ़ते हुए साम्राज्यवादी दबाव पर प्रस्ताव

13-15 मार्च 1992 को नागपुर में हुई सीटू की यह जनरल काउंसिल मीटिंग इस बात पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है कि साम्राज्यवाद विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवाद ने विश्व भर पर सैनिक, राजनीतिक व आर्थिक स्तरों पर कब्जा जमाने की अपनी मुहिम तेज कर दी है। इसी मुहिम के तहत अमरीकी साम्राज्यवाद भारत पर अपना दबाव लगातार बढ़ाता जा रहा है। भारत सरकार इसका प्रतिरोध करने के बजाय इस दबाव के समक्ष समर्पण करती जा रही है। कांग्रेस द्वारा समर्पित चन्द्रशेखर सरकार ने खाड़ी युद्ध के दौरान अमरीकी लड़ाकू जहाजों को ईंधन देने की सुविधा प्रदान की थी। नरसिम्हा राव सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में सियोनवाद को जातिवाद से अलग बताने वाले प्रस्ताव के समर्थन में मत देकर गुट निरपेक्षता की नीति को गहरा धक्का पहुंचाया जो कि अब तक भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग रही थी तथा जिसके कारण भारत को तीसरी दुनिया में प्रतिष्ठा व सम्मान हासिल हुआ था। हाल ही में अमरीकी सैनिक मिशन की भारत-अमरीका-सुरक्षा सहयोग की दृष्टि से यात्रा इस समय की सबसे आपत्तिजनक घटना है। भारत हमेशा अमरीकी साम्राज्यवाद का निशाना रहा है। अपने कुछ दक्षिण-पूर्व-एशियाई ठिकानों को खो देने के बाद अब अमरीका की नजर भारत पर है ताकि वह अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए भारतीय सुरक्षा प्रयासों की बलि चढ़ा सके।

अमरीका द्वारा आजादी के बाद से ही भारत की संस्कृति एवं विचारधारा को प्रभावित करने की कोशिशों के परिणामस्वरूप हमारी प्रेस तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया काफी प्रभावित हो चुका है। अमरीकी केबल न्यूज नेटवर्क सी.एन.एन. की शुरुआत के साथ मुहिम के नये स्तर पर पहुंच गयी है। इसका हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव है। सरकार द्वारा निजी सहयोग से एक नया चैनल शुरू करने की योजना से इस क्षेत्र में साम्राज्यवादी प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार द्वारा अमरीकी दबाव के समक्ष समर्पण करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियां भारत व अन्य विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का औजार बनाने हेतु उन पर दबाव डाल रहे हैं। इसके साथ-ही-साथ डंकल सुझाव, जो कि अमरीकी सुपर 301 तथा स्पेशल 301 के प्रसार का औजार भर है; भारत के ऊपर तलवार सा लटक रहे हैं तथा उसे धीरे-धीरे समर्पण के लिए मजबूर कर रहे हैं। हर रोज कोई न कोई तथ्य यह बतलाता है कि अवमूल्यन, व्यापार नीति, औद्योगिक नीति जिनसे बेरोजगारी आदि समस्याएं बढ़ेंगी, आदि कदम सरकार द्वारा विश्व बैंक तथा मुद्रा कोष के निर्देश पर उठाये जा रहे हैं। बजट, जो कि संसद में पेश होने तक सम्पूर्ण गोपनीयता में तैयार किया जाता है, वह भी अब विश्व बैंक-मुद्रा कोष की देखरेख में तैयार हो रहा है जिसका सीधा अर्थ अपनी नीतियां तैयार करने की देश की आजादी का समर्पण है।

सीटू की यह जनरल काउंसिल मीटिंग हमारे राष्ट्रीय जीवन पर बढ़ते हुए साम्राज्यवादी प्रभाव से चिन्तित है। सरकार द्वारा अमरीकी साम्राज्यवाद के आगे घुटने टेकने, मुद्रा कोष के निर्देश पर सरकार द्वारा अपनायी गयी खतरनाक आर्थिक नीतियाँ, देश की प्रभुसत्ता को अमरीकी साम्राज्यवाद के हाथों में सौंप देने के खिलाफ तथा इन जन विरोधी तथा राष्ट्र-विरोधी नीतियों को बदलवाने के लिए संघर्ष में आगे बढ़ाने के लिए सीटू मजदूर वर्ग तथा देश की देशभक्त जनता से अपील करती है। सीटू अपनी सभी इकाईयों से अपील करती है कि वे वर्तमान घटनाक्रम के बारे में मजदूरों तथा जनता के अन्य तबकों के बीच जबर्दस्त प्रचार अभियान चलाएं तथा एक संगठित संघर्ष के लिए व्यापक आधार तैयार करें।

जूट मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में प्रस्ताव

13-15 मार्च 1992 को नागपुर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल बैठक पश्चिम बंगाल के 2 लाख संघर्षरत जूट मजदूरों

की हड़ताल के प्रति अपना पूरा समर्थन व सहयोग व्यक्त करती है। ये मजदूर अपनी 43 सूत्रीय मांगों के लिए 28 जनवरी, 1992 से हड़ताल पर हैं। राज्य के जूट उद्योग के इन मजदूरों व श्रम संगठनों (जिनमें इंटक भी शामिल है) के इस संगठित व सतत् संघर्ष ने अन्य उद्योगों के मजदूरों को भी अपनी जायज मांगों के लिए संगठित संघर्ष के लिए प्रेरित किया है। यह बैठक पश्चिम बंगाल के जूट मजदूरों को 1969 से ही जूट मालिकों तथा उनके संगठन आई.जे.एम.ए. के आक्रमक रवैये के खिलाफ संघर्ष की राह चुनने के लिए बधाई देती है।

बैठक में चिन्ता व्यक्त की गयी कि प. बंगाल के श्रममंत्री द्वारा सद्भावनापूर्ण समझौते के अनेक प्रयासों के बावजूद मिल मालिकों को गलत तथा बेईमानी भरे रवैये के कारण मजदूरों को पिछले 47 दिनों से अपनी हड़ताल जारी रखनी पड़ रही है। ये मिल मालिक मजदूरों का भविष्यनिधि का 80 करोड़ रु. ई.एस.आई. के 40 करोड़ रु. हजम कर लिए हैं। बावजूद तमाम परेशानियों के मजदूर अपनी हड़ताल जारी रखने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। एक ओर जहां प. बंगाल की वाम मोर्चा सरकार सद्भावपूर्ण समाधान के लिए प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस (ई.) की अल्पमत केन्द्र सरकार के रवैये से मजदूरों के बीच यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि आखिर केन्द्र सरकार किसके पक्ष की घोषणा कर रही है। प्रधानमंत्री प. बंगाल के सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल को समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक कुछ नही हुआ है।

यह बैठक जूट मिल मालिकों के मजदूर विरोधी रुख तथा हड़ताली मजदूरों की समस्याओं के प्रति केन्द्र सरकार के कठोर रवैये की भर्त्सना करती है। बैठक सभी सम्बद्ध पक्षों से प. बंगाल के जूट मजदूरों की समस्याओं के तुरन्त समाधान की अपील करती है। सीटू अपनी सभी यूनियनों से अपील करती है कि वे जूट मजदूरों के संघर्ष का पूरा समर्थन करें।

निकाले गये रेलवे मजदूरों को वापस लिए जाने पर प्रस्ताव

13-15 मार्च 1992 को नागपुर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल बैठक ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भाग लेने के कारण 311 (2) (ए), (बी), (सी) के तहत नौकरी से निकाले गये सैकड़ों कर्मचारियों को वापस लेने से इन्कार करने के लिए भारत सरकार की कड़ी भर्त्सना करती है। सरकार यह भूल रही है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के शासन काल में कांग्रेस (ई) समेत पूरी संसद ने इन कर्मचारियों को वापस लिए जाने का समर्थन किया था। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के रेल मंत्री द्वारा जारी आदेश की तो बात ही छोड़िये, जिन कर्मचारियों की बहाली के लिए न्यायालय ने आदेश दिए हैं उन्हें भी किसी न किसी बहाने से बहाल नहीं किया जा रहा है।

यह बैठक सभी निकाले गये कर्मचारियों की बहाली की मांग करती है।

यह बैठक सभी राज्य इकाईयों से मांग करती है कि वे इन कर्मचारियों की बहाली के आन्दोलन का समर्थन करें तथा रेल मंत्री को विरोध तार भेजें।

कावेरी जल विवाद पर प्रस्ताव

सीटू की जनरल काउंसिल की यह बैठक सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद हल करने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी के बीच वार्ता शुरू करने में लगातार देर करने पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है। दोनों राज्यों की जनता के बीच बढ़ती हुई कटुता पर सीटू गहरी चिन्ता व्यक्त करती है क्योंकि इससे देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

जनरल काउंसिल कर्नाटक व तमिलनाडु के मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह संगठित होकर अपनी एकता व अखंडता की रक्षा करें तथा जनता के बीच रुढ़िवादी भावनाएं भड़काने के किसी भी प्रयास का डटकर विरोध करें।

सीटू कर्नाटक सरकार से मांग करती है कि वह तमिलनाडु व केरल के बेगुनाह लोगों पर आपराधिक हमले करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके सामान्य स्थिति बहाल करे ताकि वे लोग अपने घरों में वापस जा सकें। सीटू तमिलनाडु सरकार से भी मांग करती है कि कानाडिगा के सीमावर्ती इलाकों के निवासियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे तथा प्रभावितों को मुआवजा दे ताकि वे अपने घरों में वापस जा सकें। काउंसिल भारत सरकार से मांग करती है कि वह मामले को जानबूझ कर लटकाये रखना छोड़े तथा समझौते के प्रयास करे जिसमें कावेरी जल का समान बटवारा हो सके तथा दोनों पक्षों के हितों की रक्षा हो सके।

पंजाब की स्थिति पर प्रस्ताव

13-15 मार्च 1992 को नागपुर में हुई सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग पंजाब की स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है जहां साम्राज्यवाद तथा पाकिस्तान में स्थित प्रशिक्षण स्कूलों की मदद से आतंकवादी गतिविधियां एक दशक से भी अधिक से चली आ रही हैं। यह पंजाब की जनता को बधाई देती है जो इस आतंकवादी हमले का सामना कर रही है तथा उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके देश की एकता व अखंडता का झंडा ऊंचा उठाए रखा। ऐसे कई अवसर आए जब इस समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता था लेकिन भारत सरकार अपने संकीर्ण स्वार्थों के योजनाबद्ध ढंग से मामले को टालती रही तथा उसने राष्ट्रीय एकता व अखंडता की चिन्ता नहीं की। हाल के चुनावों के बाद राज्य में स्थिति और खराब हो गयी है। वामपंथी आन्दोलन द्वारा समय पर दी गयी यह चेतावनी सही साबित हुई कि यदि राज नैतिक प्रयास नहीं किए गए तो उदार अकालियों को साथ लेना संभव नहीं होगा और स्थिति में विभाजनकारी ताकतें अपने आधार को और विकसित बना देंगी। अब यह

आसानी से समझा जा सकता है कि केन्द्र की कांग्रेसी सरकार तथा राज्य के उसके सहयोगियों के दिमाग में चुनावों के समय राष्ट्रीय एकता अखंडता नही बल्कि कोई और उद्देश्य था। इसी लिए तमाम जनता को चुनावी प्रक्रिया में साथ लेने के प्रयासों के बजाय उन्होंने गाँवों में चुनाव के बायकाट को सफल बनाने में सहयोग दिया। उन्होंने आतंकवादियों के चुनाव बायकाट का अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं किया।

अब इससे हिन्दू व सिखों के बीच की खाई और बढ़ेगी। बेगुनाह लोगों की हत्याएं और बढ़ गयीं हैं। विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक मजदूरों की हत्यायें हो रही हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा बार-बार बन्द की अपील से स्थिति और बिगड़ रही है। आतंकवादियों द्वारा बलात्कार तक की घटनाएं हुई हैं लेकिन लोग डर के मारे आगे नही आ रहे हैं।

विडम्बना यह है कि कांग्रेसी शासक इसे केवल कानून व व्यवस्था की समस्या समझते हैं तथा इसे सुलझाने के लिए दमनकारी तरीके अपनाते हैं जिनकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही होती है।

सीटू जनरल काउंसिल का दृढ़ मत है कि यदि गंभीरतापूर्वक बहुआयामी प्रयास किए जाएं तो अभी भी स्थिति सुधर सकती है।

1. चंडीगढ़ तुरन्त पंजाब को सौंपा जाये।

2. जल तथा सीमा विवाद राजीव-लोंगोवाल समझौते के तहत निपटाए जायें।

3. पड़ोसी राज्यों में पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया जायें।

4. 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को सजा दी जाये।

5. इस स्थिति के कारण पंजाब की विकास प्रक्रिया में आये ठहराव को दूर किया जाये।

6. खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाये जायें लेकिन ऐसा करते समय बेकसूर लोगों को परेशान न किया जाये।

7. साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ प्रचार अभियान तेज किया जाये।

अन्त में जनरल काउंसिल मजदूर वर्ग से अपील करती है देश की एकता व अखंडता की इस लड़ाई में पंजाब की जनता व मजदूर वर्ग का समर्थन करें।

पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा की सरकार पर प्रस्ताव

13-15 मार्च 1992 को नागपुर में हो रही सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार को हार्दिक बधाई देती है। माकपा के नेतृत्व में वाम मोर्चा की लगातार चौथी बार ऐतिहासिक विजय की सराहना करती है। वाम मोर्चे द्वारा पश्चिम बंगाल में कॉ० ज्योति बसु के नेतृत्व में (जो सीटू के उपाध्यक्ष भी हैं) प्रदान की गयी स्थायी व लोकतांत्रिक सरकार अपने आप में एक मील का पत्थर ही नहीं है बल्कि देश के संसदीय क्षेत्र में भी एक अतुलनीय उदाहरण है।

उल्लेखनीय है कि जनता ने वाम मोर्चे को ऐसी सफलता अकारण ही अथवा बिना सोचे-समझे ही प्रदान नहीं की है। ऐसा अपने लम्बे शासन काल के द्वारा हासिल की गयी उपलब्धियों तथा जनोन्मुख नीतियों के कारण हुआ है। अन्य पार्टियों के विपरीत माकपा का चुनाव घोषणा पत्र केवल वोट खींचने के लिए नहीं बल्कि वाकई अमल में लाने के लिए होता है।

वाम मोर्चे की उपलब्धियां व्यापक तथा बहु आयामी हैं। सबसे महत्वपूर्ण उसके भूमि सुधार हैं। फालतू जमीन को भूमिहीनों में बाँटना वाम मोर्चा सरकार की अतुलनीय उपलब्धि है। इसी प्रकार सरकार ने अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं को भी कार्यान्वित किया है। मोर्चा सरकार के शासन काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उल्लेखनीय विकास हुआ है, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में मोर्चा सरकार ने शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं।

केन्द्र सरकार के असहयोग के बावजूद मोर्चा सरकार राज्य के औद्योगिक विकास के लिए जनता के सहयोग से अनेक उपाय कर रही है। बकरेश्वर पावर प्रोजेक्ट इसका एक शानदार उदाहरण है। सरकार ने अनेक बीमार इकाईयों को अपने हाथ में ले लिया है तथा वह उन्हें दूसरे तरीके से चला रही है। केन्द्र सरकार द्वारा निवेश न किए जाने के कारण कोई नया बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो पाया है तथा तकनीकी विकास के अभाव में अनेक इकाईयां बीमार हो गयी हैं। यह उदाहरण बताता है कि किस प्रकार केन्द्र सरकार वाम मोर्चा सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसी सन्दर्भ में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का महत्व बढ़ जाता है। वाम मोर्चा सरकार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को पुनर्संयोजन करने तथा राज्यों के हाथों में अधिक प्रशासनिक व आर्थिक अधिकार देने की मांग उठाने में अगुआ की भूमिका निभाई है। दरअसल, वाम मोर्चा सरकार से केन्द्र सरकार असहयोग ही नहीं कर रही बल्कि उसे अलोकप्रिय बनाने के लिए साजिश भी कर रही है। अतः यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यह सरकार शुरू से ही केन्द्र द्वारा पैदा की जा रही अटकलों के बीच काम कर रही है।

वाम मोर्चा सरकार द्वारा ग्रामीण प्रशासन, पंचायतों के समय पर चुनाव, शहरी क्षेत्रों के लिए जनता को सहयोग में लेकर कार्पोरेशनों व म्युनिसपैलिटियों के चुनाव आदि के माध्यम से जो जागरुकता पैदा की गयी है उसेये अच्छे सामाजिक माहौल के साथ-साथ सांप्रदायिक एकता भी सुनिश्चित हुई है। यह वाम मोर्चा सरकार की एक महान उपलब्धि है कि देश भर में व्याप्त सांप्रदायिक व विभाजनकारी गतिविधियों के समय में पश्चिम बंगाल इस बीमारी से अछूता रहा है।

वाम मोर्चा सरकार केन्द्र सरकार की जन-विरोधी नीतियों को परास्त करने में देश के लोकतांत्रिक आंदोलन के पथ-प्रदर्शक का काम कर रही है। वाम मोर्चा सरकार ने मुद्राकोष व विश्व बैंक के निर्देश पर बनी आर्थिक नीतियों के विकल्प के तौर पर एक आर्थिक नीति केन्द्र की नरसिम्हा सरकार को सुझायी थी।

जनरल काउंसिल सीटू की यूनियनों से वाम मोर्चा सरकार की इन उपलब्धियों का प्रचार करने तथा मजदूर वर्ग की सरकार की इस चौकी की रक्षा करने की अपील करती है।